



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (1)
PART II—Section 3—Sub-section (1)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 496] नई दिल्ली, रविवार, दिसम्बर 6, 1992 अग्रहायण 15 1914
No. 496] NEW DELHI, SUNDAY, DECEMBER 6, 1992/AGRAHAYANA 15, 1914

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a
separate compilation

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 दिसम्बर, 1992

सं. का. वि. 912(घ) — राष्ट्रपति द्वारा जारी की
गई निम्नलिखित उद्घोषणा सर्वसाधारण के सूचना के प्रका-
शित की जा रही है:—

यह है, मेरा, भारत के राष्ट्रपति, शंकर दयाल शर्मा का
समाधान हो गया है कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है
जिसमें उत्तर प्रदेश राज्य का शासन भारत के संविधान
(जिसे हमें हमारे पश्चात् "संविधान" कहा गया है) के
उद्देश्यों के अनुसार नहीं समझा जा सकता है,

अतः, मैं, संविधान के अनुच्छेद 356 द्वारा प्रदत्त
शक्तियों के अन्तर्गत, निम्नलिखित मुझे सौंपे जाने वाली अन्य

सभी शक्तियों को प्रयोग करते हुए एतद्वारा उद्घोषणा करता
हूँ कि मैं:—

(क) उक्त राज्य की सरकार के सभी कर्तव्य और उक्त
राज्य के राज्यपाल में निहित, तथा उनके
द्वारा प्रयोज्य सभी शक्तियाँ, भारत के राष्ट्र-
पति के रूप में स्वयं संभालता हूँ;

(ख) घोषित करता हूँ कि उक्त राज्य के विधानमंडल
की शक्तियाँ ससद् द्वारा या उसके प्राधिकार के अधीन
प्रयोज्य होंगी, और

(ग) निम्नलिखित अनुवर्षिक और पारिणामिक उप-
बन्ध करता हूँ जो इस उद्घोषणा के उद्देश्यों
का प्रभावी बनाने के लिए मुझे आवश्यक या
आवश्यक प्रतीत होते हैं, अर्थात्:—

(1) इस उद्घोषणा के उपबन्ध खंड (क) के
आधार पर मेरे द्वारा सभाने गए कृत्यों और
शक्तियों का प्रयोग करने में, मेरे लिए भारत

के राष्ट्रपति के रूप में उस सीमा तक जिस तक मैं ठीक समझू उक्त राज्य के राज्यपाल के माध्यम से कार्य करना विधिपूर्ण होगा;

- (ii) उक्त राज्य के संबंध में संविधान के निम्नलिखित उपबंधों के प्रवर्तन को एतद्वारा निरांकित किया जाता है; अर्थात्:—

अनुच्छेद 3 के परन्तुक का उतना भाग जितने का संबंध राष्ट्रपति द्वारा राज्य के विधानमंडल को निदेश करने से है;

अनुच्छेद 151 के खंड (2) का उतना भाग जितने का संबंध भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक द्वारा राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत किए गए प्रतिवेदनों को राज्य विधानमंडल के समक्ष रखे जाने से है;

अनुच्छेद 163 और 164;

अनुच्छेद 166 का खंड (3) का उतना भाग जितने का संबंध मंत्रियों के बीच राज्य सरकार के कार्य के आबंधन से है;

अनुच्छेद 167;

अनुच्छेद 169 के खंड (1) का उतना भाग जितने का संबंध राज्य की विधान सभा द्वारा संकल्प को पारित करने से है;

अनुच्छेद 174 का खंड (1), और खंड (2) का उपखंड (क); अनुच्छेद 175 से 178 तक (जिसमें ये दोनों सम्मिलित हैं);

अनुच्छेद 179 के खंड (ख) और (ग) और उस अनुच्छेद का प्रथम परन्तुक;

अनुच्छेद 180, 181 और 182; अनुच्छेद 183 का खंड (ग) और उसका परन्तुक;

अनुच्छेद 185;

अनुच्छेद 186 का उतना भाग जितने का संबंध विधान सभा के उपाध्यक्ष के वेतनों और भत्तों से है;

अनुच्छेद 187 के खंड (3) का उतना भाग जितने का संबंध विधान सभा के अध्यक्ष के साथ परामर्श से है;

अनुच्छेद 188 का उतना भाग जितने का संबंध विधान सभा के सदस्यों से है;

अनुच्छेद 189, 193 और 194;

अनुच्छेद 195 का उतना भाग जितने का संबंध विधान सभा के सदस्यों के वेतनों और भत्तों से है;

अनुच्छेद 196 से 198 तक (जिसमें ये दोनों सम्मिलित हैं);

अनुच्छेद 199 के खंड (3) और (4);

अनुच्छेद 202 के खंड (3) का उतना भाग जितने का संबंध विधान सभा के उपाध्यक्ष के वेतनों और भत्तों से है;

अनुच्छेद 208 से 211 तक (जिसमें ये दोनों सम्मिलित हैं);

अनुच्छेद 213 के खंड (1) का परन्तुक और खंड (3) का परन्तुक; और

अनुच्छेद 323 के खंड (2) का उतना भाग जितने का संबंध शासन संहिता रिपोर्ट के राज्य के विधानमंडल के समक्ष रखे जाने से है;

- (iii) उक्त राज्य की विधान सभा एतद्वारा भंग की जाती है;

- (iv) संविधान में राज्यपाल के प्रति किसी निदेश का अर्थ उस राज्य के संबंध में राष्ट्रपति के प्रति निदेश लगाया जाएगा और उसमें राज्य के विधानमंडल या उसके सदस्यों के प्रति किसी निदेश का, जहाँ तक उसका संबंध उसके कुर्यों और उसकी शक्तियों से है, अर्थ, जब तक कि संदर्भ द्वारा अन्यथा अंग्रेजित न हो, संसद् के प्रति निदेश लगाया जाएगा और विधिद्वारा अनुच्छेद 213 में राज्यपाल और राज्य के विधानमंडल या उसके सदस्यों के प्रति निदेश का अर्थ क्रमशः राष्ट्रपति और संसद् या उसके सदस्यों के प्रति निदेश लगाया जाएगा;

परन्तु इसमें कोई बात अनुच्छेद 153, अनुच्छेद 155 से लेकर अनुच्छेद 159 तक (जिसमें ये दोनों सम्मिलित हैं); अनुच्छेद 299 और अनुच्छेद 361 तथा द्वितीय अनुच्छेदों द्वारा 1 से लेकर पैरा 4 तक (जिसमें ये दोनों सम्मिलित हैं) के उपबंधों पर प्रभाव नहीं डालेगी और न राष्ट्रपति को उस खंड के उपखंड (1) के अधीन उस सीमा तक जहाँ तक वह ठीक समझे उक्त राज्य के राज्यपाल के माध्यम से कार्य करने से निवारित करेगी;

- (v) संविधान में राज्य के विधानमंडल के दंड उसके द्वारा बनाए गए अधिनियमों या विधियों के प्रति किसी निदेश का ऐसे अर्थ लगाया जाएगा मानों वह उन अधिनियमों और विधियों को समाविष्ट करता है जो इस उद्घोषणा के आधार पर संसद् द्वारा या राष्ट्रपति या संविधान के अनुच्छेद 357 के

खंड (1) के उपखंड (क) में निर्दिष्ट अन्य प्राधिकारी द्वारा राज्य के विधान मंडल की शक्तियों का प्रयोग करते हुए बनाए गए हैं और संयुक्त प्रान्त सामान्य खंड अधिनियम 1904 (1904 का यू.पी. अधिनियम 1) और सामान्य खंड अधिनियम, 1897 (1897 का 10) का उना भाग जिसका राज्य की विधियों पर लागू है ऐसे किसी अधिनियम या विधि के बारे में इस प्रकार प्रभावी होगा मानों यह उन राज्य के विधान-मंडल का अधिनियम हो।

नई दिल्ली,

शंकर दयाल शर्मा

दिनांक : 6 दिसम्बर, 1992

राष्ट्रपति

[फा.सं. 5/11013/17/92-सी.एम.भार.]

माधव गोडबोले, गृह सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th December, 1992

G.S.P. 912(E).—The following Proclamation by the President is published for general information :—

Whereas, I Shanker Dayal Sharma, President of India, am satisfied that a situation has arisen in which the Government of Uttar Pradesh cannot be carried on in accordance with the provisions of the Constitution of India (hereinafter referred to as "the Constitution");

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by article 356 of the Constitution and of all other powers enabling me in that behalf, I hereby proclaim that I—

- (a) assume to myself as President of India all functions of the Government of the said State and all powers vested in or exercisable by the Governor of that State;
- (b) declare that the powers of the Legislature of the said State shall be exercisable by or under the authority of Parliament; and
- (c) make the following incidental and consequential provisions which appear to me to be necessary or desirable for giving effect to the objects of this Proclamation, namely :—
 - (i) In the exercise of the functions and powers assumed to myself by virtue of clause (a) of this Proclamation as aforesaid, it shall be lawful for me as President of India to act to such extent as I think fit through the Governor of the said State;

(ii) the operation of the following provisions of the Constitution in relation to that State is hereby suspended, namely :—

so much of the proviso to article 3 as relates to the reference by the President to the Legislature of the State;

so much of clause (2) of article 151 as relates to the laying before the Legislature of the State of the report submitted to the Governor by the Comptroller and Auditor-General of India;

articles 163 and 164;

so much of clause (3) of article 166 as relates to the allocation among the Ministers of the business of the Government of the State;

article 167;

so much of clause (1) of article 169 as relates to the passing of a resolution by the Legislative Assembly of a State;

clause (1) and sub-clause (a) of clause (2) of article 174;

articles 175 to 178 (both inclusive);

clause (b) and (c) of article 179 and the first proviso to that article;

articles 180, 181 and 182, clause (c) of article 183 and the proviso thereto; article 185;

so much of article 186 as relates to the salaries and allowances of the Deputy Speaker of the Legislative Assembly;

so much of clause (3) of article 187 as relates to consultation with the Speaker of the Legislative Assembly;

so much of article 188 as relates to a member of the Legislative Assembly;

articles 189, 193 and 194;

so much of article 195 as relates to the salaries and allowances of Members of the Legislative Assembly;

articles 196 to 198 (both inclusive); clauses (3) and (4) of article 199;

so much of clause (3) of article 202 as relates to the salaries and allowances of the Deputy Speaker of the Legislative Assembly; articles 208 to 211 (both inclusive);

the proviso to clause (1) and the proviso to clause (3) of article 213; and

so much of clause (2) of article 323 as relates to the laying of the report with a memorandum before the Legislature of the State;

(iii) the Legislative Assembly of the said State is hereby dissolved;

(iv) any reference in the Constitution to the Governor shall, in relation to the said State be construed as a reference to the President, and any reference therein to the Legislature of the State or the Houses thereof shall, in so far as it relates to the functions and powers thereof, be construed, unless the context otherwise requires, as a reference to Parliament, and, in particular, references in article 213 to the Governor and to the Legislature of the State or the Houses thereof, shall be construed as references to the President and to Parliament or to the Houses thereof respectively :

Provided that nothing herein shall affect the provision of article 153, articles 155 to 159 (both inclusive), article 299 and article 361 and paragraphs 1 to 4 (both inclusive) of the Second Schedule or prevent the President from acting under sub-clause (i) of this clause to such extent as he thinks fit through the Governor of the said State,

(v) any reference in the Constitution to Acts or laws of or made by the Legislature of the State shall be construed as including a reference to Acts or laws made in exercise of the powers of the Legislature of the State, by Parliament by virtue of this Proclamation, or by the President or other authority referred to in sub-clause (a) of clause (1) of article 357 of the Constitution and the United Provinces General Clauses Act, 1904 (U P Act No 1 of 1904), and so much of the General Clauses Act, 1897 (10 of 1897), as applies to State laws, shall have effect in relation to any such Act or law as if it were an Act of the Legislature of the State

SHANKER DAYAL SHARMA

PRESIDENT

New Delhi
Dated December 6, 1992

[F No. V/11013/17/92-CSR]

MADHAV GODBOLE, Home Secretary

आदेश

नई दिल्ली, 6 दिसम्बर, 1992

सा.का.नि 913(प्र):—राष्ट्रपति द्वारा जारी किया गया निम्नलिखित आदेश सर्वसाधारण के सूचनार्थ प्रकाशित किया जा रहा है:—

भारत के संविधान के अनुच्छेद 356 के अधीन मेरे द्वारा आज दिसम्बर के छठे दिन जारी की गई उद्घोषणा के खंड (ग) के उपखंड (1) का अनुसरण करते हुए, मैं एतद्वारा निदेश देता हूँ कि उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के सभी कृत्य और संविधान के अधीन या उस राज्य में प्रचलित किसी विधि के अधीन उस राज्य के राज्यपाल ने निहित या उसके द्वारा प्रयोज्य सभी शक्तियाँ, विभिन्नको, राष्ट्रपति ने उक्त उद्घोषणा के खंड (क) के आधार पर स्वयं संभाल लिया है, राष्ट्रपति के अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण के अध्वधीन रहते हुए, उक्त राज्य के राज्यपाल द्वारा भी प्रयोज्य होंगी।

नई दिल्ली,
दिनांक 6 दिसम्बर, 1992

शंकर दयाल शर्मा
राष्ट्रपति

[फा सं 5/11013/17/92-सी एस आर]

माधव गोडबोले, गृह सचिव

ORDER

New Delhi, the 6th December, 1992

G.S.R. 913(E)—The following Order by the President is published for general information:—

In pursuance of sub-clause (i) of clause (a) of the Proclamation issued on this the 6th day of December 1992 by me under article 356 of the Constitution of India, I hereby direct that all the functions of the Government of the State of Uttar Pradesh and all the powers vested in or exercisable by the Governor of that State under the Constitution or under any law in force in that State, which have been assumed by the President by virtue of clause (a) of the said Proclamation, shall, subject to the superintendence, direction and control of the President, be exercisable also by the Governor of the said State.

SHANKER DAYAL SHARMA
PRESIDENT

New Delhi
Dated December 6, 1992.

[F. No. V/11013/17/92-CSR]

MADHAV GODBOLE, Home Secretary